PLAN. OUTLAY FOR BIHAR FOR 1986-87

264. SHRLMAT1 PRATIBHA SINGH

SHRI RAMCHANDRA BHARA-DWAJ:

Will the PRIME MINISTER be pleased be pleased to state:

(a) whether the annual plan for 19S6-87 for Bihar been finalised;

(b) if so, what are the details of the plan outlays as compared to that demanded by the State Government under each sector; and

(c) what were the outlays for 1985-86?

THE MINISTER OF STATE LN THE MINISTRY OF PLANNING AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Annual Plan 1986-87 *Bihar*

(Rs. lakhs)

Head of Development	1985-86	1986-87	Outlay
	Approved Outlay	Proposed by the State Govt.	As Agreed
(1) Agriculture & Allied Services	4617	7100	6886
(2) Rural Development	8413	10050	10541
(3) Special Area Programmes	..	..	1500
(4) Irrigation & Flood Control	27500	34335	34539
(5) Energy	16000	25245	23725
(6) Industry & Minerals	3300	5653	5603
(7) Transport	7205	9417	9150
(8) Science, Technology & Environment	85	71	71
(9) General Economic Services	383	8001	2134
(10) Social Services	16022	20619	18618
(11) General Services	1595	2759	2233
GRAND TOTAL	85100	123250	115000

io was actually asked on the floor of the House by Sharimati Pratibha Singh.

श्रीमती प्रतिभा सिंह श्रीमान, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि 1985–86 में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक राशि हमें मिली है प्रत्येक सैक्टर के लिए किन्तु जो सामान्य अधिक सेवाएं आपने 9वें आइटम में दी है, उनके लिए आपने बिहार को कम राशि दी है। हम लोगों ने 8,000 लाख रुपए मांगे थे किन्तु आपने केवल 2134 लाख रुपए निर्धारित किए हैं तो ऐसा क्यों हुआ ?

SHRI AJIT PANJA: Sir, while deciding the Plan allocation, certain formula is adopted. Now, the modified Gadgil formula is being adopted. In respect of a particular State or Union Territory, we consider the entire population and wen the area where major thrust has to be given. So far as Biha$_r$ is concerned, it is 1.74 rakhs Sq. Kms. The number of villages is 67,665 and the population is 699 lakhs. While calculating, we found that the rural population is 87.5 per cent. Therefore, as regard, as given in the state-rant, we impressed on the Chief Minuet and other officers of Bihar who came that more thrust should be in the area of rural development. That is why, Sir, you will see that in the case of rural development, even though the approved outlay for 1985-86 was Rs. 8413 lakhs, the proposal of the State was Rs. 10,050 lakhs, the Planning Commission increased it to Rs. 10,541 lakhs. We decided that more money should go from the general economic services to the rural areas for the benefit of the poor.

श्रीमती प्रतिभा सिंह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जबकि यह सही है कि रूरल डेवलेपमेंट के लिए अधिक राशि आबंटित की गई इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है और केन्द्रीय सरकार को भी धन्यवाद है यह विशेष हमारे प्रधान मंत्री जी की वजह से ही हुआ है क्योंकि उनका ध्यान रूरल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा है लेकिन साथ ही में यह जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय को यह नहीं मालूम है जैसा उन्होंने बताया कि पापुलेशन इतनी है, एरिया इतना है, सब कुछ बताया जबकि बिहार इकोनोमिक डेवलेपमेंट में बहुत पीछे है। बिहार सबसे पिछडा प्रदेश है यद्यपि वहां पर खनिज पदार्थ भी हैं, वाटर रिर्सोसिज भी हैं, पानी भी है लेकिन कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। कहीं भी कुछ नहीं हुआ ? लेकिन ऐसी विशेष परि-स्थिति में क्या यह उचित नहीं था कि मंत्री महोदय इस पर अधिक राशि देते ताकि बिहार भी जो डेवलपमेंट स्टेटस हैं यदि उनके बराबर न हो सके तो कम से कम आसपास तो आ सके ?

SHRI AJIT PANJA: Sir, it is true, so far Bihar is concerned, the per capita income is the lowest in the whole of India. It is Rs, 437 as against the all-India average of 761. But I would like to point out to the hon. Member that 'General Economic Services' doe$_s$ not include industry and minerals. Hon. Member wanted to know about the minerals sector, and about the industries. This has been specifically mentioned in the statement at item no. 6 (VI). The approved outlay for 1985-86 was Rs. 3300 lakhs and the agreed outlay for 1986-87 is Rs. 5603 need for development of the industry and lakhs. Therefore, we are aware of the need for development of the industry and minerals sector.

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इन्होंने जो पर-कैपिटा इन्कम हमारे बिहार की बताई क्या वह 1970–71 की प्राइसेज पर बताई या आज की प्राइसेज पर बताई ? क्योंकि आज के प्राइसेज के मुता-बिक तो यह और भी कम हो सकता है ?

SHRI AJIT PANJA; It is per capita income for 1983-84 at 1970-71 prices.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को, अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि परिव्यय योजना में बिहार के प्रति विशेष उदारता बरती है। बिहार शायद इसका अधिकारी भी है क्योंकि अत्यन्त पिछड़ा हुआ राज्य है। मैं सिर्फ यह

निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी जो कुछ राशि हमें आवंटित कर देते हैं, जो कुछ राशि हम को दे देते हैं, पिछले दिनों में हमारा यह अनुभव रहा है कि लूटपाट आदि के कारण वहां काम नहीं हो पाया है और उस राशि को डाइवर्ट भी किया गया है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई रास्ता है कि वे इस बात पर निगरानी रखें कि जिस काम के लिए राशि दी गई है उसी काम में खर्च हो रही है या नहीं ? इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों, महिलाओं और व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या विशेष योजना बनाई गई है ?

SHRI AJIT PANJA: So far as the first part of the question is concerned, under the specific directions of the hon'ble Prima Minister, every 3 months quarterly monitoring is a must. But the primary duty i_s of the State for doing it. So far as Planning Commission is concerned, after the State obtains .this monitoring report, we get a feed-back from them. But we are insisting that they must continue this monitoring, not only regarding expenditure of th_e amount but also how much physical achievement of various development plans has been attended to.

So far as diversion of funds is concerned, specific instructions have been issued by the Finance Department that if the allocated sum for a specific purpose in a certain sector is diverted, then an equal percentage of Central assistance would be deduc'ed from them. This is a penal clause like a Damocles' sword which hangs over them that if they do from the Central assistance on a percen-so, then we have this right to deduct it tage basis.

So far as scheduled castes and scheduled tribes are concerned, we find that in Bihar in the total population, the scheduled caste is 14.5 per cent and scheduled tribe is 8.3 per cent. So far as specific allocation for them is concerned, there are various tribal sub-plan projects done so that we can have a major thrust *in* these areas and under the 20-point economic programme, the major beneficiaries are within these areas and they are going to get benefit from this.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी, बिहार की आबादी 7 करोड हो गई है : इस प्रदेश में रेलों की संख्या भी उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर है : इसी कारण से वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी अधिक नही है। बिहार में रेल लाइनें कम हैं, सडकें कम हैं, बिजली की खपत कम है और लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, यद्यपि बिहार में पानी बहुत है। इन सब चीजों पर विचार करने की जरुरत है। बिहार की स्थिति का दिग्दर्शन अभी श्री भारद्वाज जी ने किया है। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर करोडों की आजादी है वहां पर लोगों को सुविधाएं प्रदान की जायें, पेय जल की सुविधा प्रदान की जाय उनके पास प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। बिहार के लोगों को पर्याप्त पोष्टिक भोजन भी नहीं मिलता है। उनका बिजली का कन्जम्पशन बढ सके, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। अभी हालत यह है कि वहा के उद्योग धन्धे बढ़ते जा रहे बिहार को अभी खनिज पदार्थों की रायल्टी भी उचित दर पर प्राप्त नहीं होती है। इसलिए में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के पिछडेपन को देखते हुए क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि बिहार को साधन मिल सकें ताकि बिहार उन साधनों को अपने विकास में खर्च कर सके ? क्या आप बिहार में इंफ्रास्ट्रचर डेवलप करने के लिए कोई तैयारी करेंगें, मोनिटरिंग करेंगे ?

SHRI AJIT PANJA: Sir, this i_s mainly a request for action. But so far as the first portion regarding water supply is concerned, we have identified 15194 villages. When I say "we" I mean the State gave u_s this figure of problem villages. Out of this, in the Sixth Plan partially 14172 villages have been provided with drinking water. For the balance 1022 villages, it i_s provided ia the Seventh Plan.

So far as the other request for action about monitoring is concerned, I have already replied to that.

श्री सत्यपाल मलिक : चेयरमैन साहब असल में गलत मुद्दे पर बहस हो रही है। मुगल बादशाह हर शनिवार को खैरात बांटते थे और बहुत बड़े पैमाने पर बांटते थे, लेकिन उससे देश का विकास नहीं हुआ : सवाल यह नहीं है कि आप कितनी राशी परिव्यय के लिए स्वीकार करते हैं : पिछले महीने प्रधान मंत्री जी ने सही बहस शुरु की कि हम यह जाने कि जो रुपया दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं : उसका कहीं डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है ? गलत जगह डाइवर्ट । नहीं हो रह है, पापुलिस्ट कामों के लिये तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जान ना चाहूंगा कि इस साल जो अपने अलोकेशने किया है राज्य सरकारों को तो किन किन राज्यों को आपने इस दृष्टि से चेतावनी दी है और जिन्होंने अपने पापुलिस्ट कामों के लिये विकास का रुपया डाइवर्ट किया है उन राज्यों का नाम मैं जानना चाहूंगा ?

दूसरा, मोनेटरिंग करते समय क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी मिली कि पश्चिमी बंगाल में रुपि का मामला बिल्कुल ठप्प हो गया है ।

MR. CHAIRMAN:; This relates to Bihar.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, is it relevant?. .. *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: He answered the question about monitoring several times. Dr. Richhariya.

डा० गोविन्द दास रिछारिया : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं उन्होंने माना है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी कम है तो क्या वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उसका कम होने का कारण यह है कि पहली योजना से छठी योजना तक जो व्यय बिहार में या इसी तरह के जो बड़ी आबादी वाले प्रदेश है, उनमें आबादी के हिसाब से नहीं किया गया है ? इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सातवीं योजना में, जब तक बिहार और देश के दूसरे बड़ी आबादी वाले प्रदेश बराबरी पर नहीं आ जाते हैं तब तक उसको विशेष मदद दी जायेगी और इस बात की कोशिश की जायेगी कि बिहार और दूसरे अन्य प्रदेश, जो बड़ी आबादी के हैं वह अन्य प्रदेशों की तुलना में बराबरी पर आ जांय ।

SHRI AJIT PANJA: Sir, it is not a question of my admission of the per capita income; it is a fact. Secondly, it is not correct that from the First Plain onwards proper emphasis was not given. Economists at that time found certain priorities and political leaders also found certain priorities. With the development of our knowledge we are finding other areas for development and having major thrusts as presently advised by economists. You will find that so far as special assistance for Bihar is concerned, i_n the Sixth Plan Central assistance was 39.1 per cent and in the Seventh Plan it has been made 44.9 per cent because we took into Gov-sidefation the difficultiec of the Bihar Gov. ernment in augmenting internal resour-ces. But that does not mean that they won't do anything on their behalf and put the entire burden on the Centre. Of course, Centre gets the money from all over the country but it has been accele-raed and, as I said, the percentage has been given. So far as outlay is concerned, in the Sixth Plan it was Rs. 3,225 crores and in the Seventh Plan it was R's. 5,100 crores.

Proposal to make zonal cadres for IAS[IPS Officers

*265. SHRI V. GOPALSAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

,(a) whether Government have a proposal to mak_e changes in the cadre-allocation of IAS]IPS officers among States and make it zonal based;